

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167]

दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 4, 2015/अग्रहायण 13, 1937

[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 159

No. 167]

DELHI, FRIDAY, DECEMBER 4, 2015/AGRAHAYANA 13, 1937

[N.C.T.D. No. 159

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2015

2015 का विधेयक संख्या 23

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का 3) का पुनः संशोधन करने हेतु

एक

विधेयक

सं. 21(23)/वैट/(तृ.संशो)/2015/वि.स.स. IV/वि./7402.—इसे भारतीय गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जायेगा :—

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ :— (1) इस अधिनियम को दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।
- (2) यह संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होगा।
- (3) यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना से सरकार द्वारा यथानियत तिथि को प्रभावी होगा।

शर्त है कि इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिये भिन्न-भिन्न तिथियां नियत की जा सकेंगी।

2. धारा 3 का संशोधन :— दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (इसके बाद यहां "मूल अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 3 में उपधारा (10) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा को सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात्—

"(11) इस अधिनियम में किसी विपरित उपबंध के होते हुए भी, सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसी वस्तुओं को विनिर्दिष्ट कर सकती है जिनपर कोई व्यक्ति जब भारत के बाहर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उन वस्तुओं का आयात करता है तो सरकार द्वारा अधिसूचित दरों पर अग्रिम कर का भुगतान करेगा परन्तु यह दर अधिनियम के अंतर्गत उन वस्तुओं पर लागू दरों से अधिक नहीं होगी। उपरोक्त अग्रिम भुगतान किये गए कर की गणना के कर दायित्वों में की जायेगी।

उपबंध है कि सरकार अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्ति वर्ग को अग्रिम कर के भुगतान से छूट दे सकती है या अग्रिम दिए जाने वाले कर के भुगतान की दर को कम कर सकती है जिस पर अधिसूचित शर्तें लागू होंगी:

आगे उपबंध है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर आयुक्त या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी मामले के सभी पहलुओं की जांच करके इस निर्णय पर पहुंचता है कि संबंधित व्यक्ति को अग्रिम कर भुगतान से छूट दी जायेगी या अग्रिम कर भुगतान कर दर कम कर दी जाये तो वह उस व्यक्ति पर यथोचित शर्तें लगाकर ऐसा कर सकता है।

**स्पष्टीकरण:**—जो व्यक्ति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वस्तुओं का आयात करता है इस धारणा पर अग्रिम कर का भुगतान करेगा कि ऐसा सामान बिक्री या विनिर्माण में उपयोग या बिक्री हेतु सामान के प्रक्रमण हेतु आयात की गई है जब तक वह अन्यथा सिद्ध न कर दे। यह भी धारणा हो सकती है जब तक संबंधित व्यक्ति अन्यथा सिद्ध नहीं करता कि ऐसा सामान या उससे विनिर्मित कोई उत्पाद उस मूल्य से कम पर नहीं बेचा जायेगा जिस मूल्य पर सामान खरीदा गया तथा आयात किया गया है।

3. **धारा 29 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 29 में उपधारा (1), के पश्चात् तथा स्पष्टीकरण 1 खंड से पहले निम्नलिखित उपधारा सन्निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :-

“(2) आयुक्त सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट तिथि से किसी व्यापारी या व्यापारी वर्ग को आवश्यक रूप से केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिटर्न जमा करने के लिए कह सकता है जिस पर डिजिटल हस्ताक्षर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक पहचान प्रक्रिया संलग्न हो।”

4. **नई धारा का सन्निवेश.**— मूल अधिनियम की धारा 50 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा सन्निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :-

“50क बिक्री सूचना का इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण.— (1) सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी व्यापारी या व्यापारी वर्ग को बिक्री इन्चाइस की सूचना आयुक्त को देने के लिए तत्काल संप्रेषण के लिए आवश्यक समझे जाने वाले ऐसी अनुपालन उपकरण या साफ्टवेयर को लगाने के लिए कह सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन यथापेक्षित उपकरण उसकी स्थापना तथा साफ्टवेयर की लागत व्यापारी द्वारा वहन की जायेगी।”

5. **धारा 89 का संशोधन .**—मूल अधिनियम की धारा 89 में—

(i) उपधारा (1) में अन्तिम शब्द “अर्थदंड के साथ” को “ऐसा अर्थदंड जिसकी राशि कर न्यूनता के बराबर राशि से कम नहीं होगी या पचास हजार रुपये, जो अधिक हो, परन्तु कर न्यूनता की राशि से चार गुणा से अधिक नहीं होगी।”

(ii) उपधारा (2) में अन्तिम शब्द “अर्थदंड के साथ” को “ऐसा अर्थदंड जिसकी राशि कर न्यूनता के बराबर राशि से कम नहीं होगी या पचास हजार रुपये, जो अधिक हो, परन्तु कर न्यूनता की राशि से चार गुणा से अधिक नहीं होगी।”

(iii) उपधारा (3) के लिये निम्नलिखित उपधारा को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(3) इस अधिनियम के अधीन जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से कर भुगतान अर्थदंड या ब्याज या इन सभी की वंचना करने का जानबूझ कर प्रयास करेगा उसे अपराधी पाये जाने पर दंड इस प्रकार होगा—

(क) ऐसे किसी मामले में जहां एक वर्ष की अवधि के दौरान एक करोड़ रुपये से अधिक राशि शामिल है न्यूनतम छह मास से दो वर्ष का कठोर कारावास तथा एक राशि जो कर न्यूनता से कम न हो, के बराबर या पचास हजार रुपये, जो अधिक हो, परन्तु संबंधित कर न्यूनता की राशि से चार गुणा से अधिक न हो।

(ख) ऐसे किसी मामले में जहां एक वर्ष की अवधि के दौरान पचास हजार रुपये लेकिन एक करोड़ रुपये से कम की राशि शामिल है न्यूनतम छह मास तक का कठोर कारावास तथा एक राशि जो कर न्यूनता से कम न हो, के बराबर या पचास हजार रुपये, जो अधिक हो, परन्तु संबंधित कर न्यूनता की राशि से चार गुणा से अधिक न हो।

(ग) ऐसे किसी अन्य मामले में तीन मास तक का कठोर कारावास तथा एक राशि जो कर न्यूनता से कम न हो, के बराबर या पचास हजार रुपये, जो अधिक हो, परन्तु संबंधित कर न्यूनता की राशि से चार गुणा से अधिक न हो।

(iv) उपधारा (4) में अन्तिम शब्द “अर्थदंड के साथ” को “ऐसा अर्थदंड जिसकी राशि कर न्यूनता के बराबर राशि से कम नहीं होगी या पचास हजार रुपये, जो अधिक हो, परन्तु कर न्यूनता की राशि से चार गुणा से अधिक नहीं होगी।”

(v) उपधारा (5) में अन्तिम शब्द “अर्थदंड के साथ” को “ऐसा अर्थदंड जिसकी राशि कर न्यूनता के बराबर राशि से कम नहीं होगी या पचास हजार रुपये, जो अधिक हो, परन्तु कर न्यूनता की राशि से चार गुणा से अधिक नहीं होगी,” तथा

(vi) उपधारा (6) में “एक सौ रुपये” शब्दों को “पांच सौ रुपये” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

6. **नयी धारा का सन्निवेशन.**—मूल अधिनियम की धारा 91 के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा सन्निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :-

“91क विशेष न्यायालय एवं लोक अभियोजक.—(1) इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल प्रावधान के होते हुए भी सरकार यदि समीचीन या आवश्यक समझती है तो इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक विशेष न्यायालय का गठन कर सकती है।

(2) विशेष न्यायालय के लिए, सरकार एक व्यक्ति को लोक अभियोजक के रूप में तथा एक से अधिक व्यक्तियों को अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त कर सकती है।”

7. धारा 92 में संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 92 में—

(i) उपधारा (2) में अन्तिम शब्द “कोई संज्ञेय अपराध” के पश्चात् “तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के सभी प्रावधान यथोचित परिवर्तन के साथ लागू होंगे” शब्दों को सन्निविष्ट किया जायेगा; तथा

(ii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारों को सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

“(3) यदि किन्हीं कार्यों का अनुक्रम ऐसा हो कि वह एक ही विनियम का रूप ले, तो भारतीय दंड संहिता, 1860 के अंतर्गत किसी संज्ञेय अपराध को इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराध के अतिरिक्त माना जायेगा।

(4) ऐसा प्रत्येक अधिकारी या इसके लिए प्राधिकृत व्यक्ति अपराध की जांच करने पर मुकदमा चलाने की संस्वीकृति देने या अन्यथा रूप में आयुक्त को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तथा आयुक्त प्रस्तुत मामले में मुकदमा चलाना आवश्यक है अथवा नहीं इस पर निर्णय करते हुए उस क्षेत्र में क्षेत्राधिकार रखने वाले मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष या सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से नामित न्यायालय के समक्ष मुकदमा दायर करवाएगा।

8. धारा 93 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 93 में उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक को सन्निविष्ट किया जायेगा; अर्थात् “प्रावधान है कि समान प्रकृति के दोबारा और तत्पश्चात् अपराध पर संयोजन लागू नहीं होगा”।

#### उद्देश्यों और कारणों का विवरण

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 में ऐसा संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है जिससे ऐसे विशिष्ट प्रावधान शामिल किए जा सकें जिनकी आवश्यकता विभिन्न बाध्यकारी कारणों से हो गई थी जैसे विभाग द्वारा पाई गई या समय-समय पर हितधारकों द्वारा जानकारी में लाई गई असंगतियों/अनियमितताओं को समाप्त करना तथा कर प्रशासन अधिक कुशल बनाने तथा जनहित की दृष्टि से अपेक्षित कुछ परिवर्तन किया जाना।

धारा 3 का में प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य भारत से बाहर से सामान का आयात करने वाले व्यक्तियों से अग्रिम करारोपण तथा वसूली तथा आयातकों द्वारा कर वचना की संभावनों को न्यूनतम करके कर प्रशासन को अधिक कुशल बनाना है।

धारा 29 में प्रस्तावित संशोधन से व्यापारियों को डिजिटल हस्ताक्षरों या अन्य इलेक्ट्रॉनिक विकल्पों द्वारा रिटर्न दायर करने की सुविधा प्राप्त होगी जिससे विभाग में डी वेट 56 फार्म में व्यक्तिगत रूप में भरने की अपेक्षा समाप्त होगी।

नयी धारा 50क का उद्देश्य व्यापारियों द्वारा की जाने वाली बिक्री के आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण के माध्यम से तत्काल प्राप्त करना और इसके बाद में बिक्री आंकड़ों में हेराफेरी की संभावनों तथा कर वचना को न्यूनतम करना है।

धारा 89 में संशोधन से संभावित कर वंचकों के लिए दंड में बढ़ोतरी करके अधिक कठोर प्रावधान बनाना है जिसमें दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 के प्रावधानों में न्यूनतम दंड की राशि में बढ़ोतरी करना भी शामिल है।

नयी धारा 91क के सन्निवेशन का प्रस्ताव अपराधों पर द्रुत मुकदमा चलाने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना हेतु सक्षम बनाने के प्रावधान के लिए है।

धारा 92 के प्रस्तावित संशोधन का लक्ष्य भारतीय दंड संहिता, 1860 के अधीन जांच का अधिकार प्रदान करना है जहां दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 के अधीन अपराध होने पर भारतीय दंड संहिता, 1860 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होना माना जायेगा तथा किसी अपराध की जांच के पश्चात् मुकदमा चलाने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया भी शामिल की गई है।

धारा 93 में संशोधन आदतन अपराधियों के अपराधों की पुनरावृत्ति को समाप्त करने के लिए है।

इस विधेयक का उपरोक्त उद्देश्य है।

#### वित्तीय ज्ञापन

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015 में किसी प्रकार की वित्तीय जटिलताएं सम्मिलित नहीं हैं, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की समेकित निधि से नए पदों पर कोई खर्च अपेक्षित नहीं है।

#### प्रत्यायोजन विधान से संबंधी ज्ञापन

मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015 में निम्नलिखित के अलावा कोई अधीनस्थ विधान बनाने के लिये किसी अधिकारी को शक्तियों के प्रत्यायोजन का प्रावधान नहीं रखा गया है—

(i) इस अधिनियम की धारा 2 के अधीन वस्तुओं का विनिर्देशन तथा उन पर अग्रिम कर की दरें, अग्रिम कर की वसूली की शर्तें तथा पद्धति के लिये प्रत्यायोजन।

(ii) इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन डिजिटल हस्ताक्षरों या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक पहचान प्रक्रिया के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से रिटर्न भरने की अपेक्षा संबंधी प्रत्यायोजन।

(iii) इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन फिजिकल कम्प्लायंस डिवाइस या सॉफ्टवेयर के माध्यम से बिक्री इन्वाइस की तुरन्त सूचना प्राप्त करने के लिये प्रत्यायोजन।

(iv) इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिये प्रत्यायोजन।

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा, सचिव

## DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

## NOTIFICATION

Delhi, the 4th December, 2015

## BILL NO. 23 OF 2015

## THE DELHI VALUE ADDED TAX (THIRD AMENDMENT) BILL, 2015

A

BILL

to further amend the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (3 of 2005).

**No. 21(23)/VAT (3rd A)/2015/LAS-IV/Leg./7402.**—Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-sixth year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title, extent and commencement.**—(i) This Act may be called the Delhi Value Added Tax (Third Amendment) Act, 2015.

(ii) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(iii) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act.

**2. Amendment of section 3.**—In the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 3, after sub-section (10), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(11) Notwithstanding anything contained in this Act to the contrary, the Government may by notification specify the goods on which a person shall pay tax in advance at the rates notified by the Government but not exceeding the rates applicable on such goods under this Act, when he imports such goods into the National Capital Territory of Delhi from a place outside India, subject to such conditions as may be specified in the notification. The aforesaid payment of tax in advance shall be counted towards the final tax liability of the taxable person:

Provided that the Government may by notification exempt any person or class of persons from payment of tax in advance or reduce the rate of payment of tax in advance subject to such conditions as may be notified:

Provided further that if on an application made by a person the Commissioner or an officer authorized by him, after verifying all aspects of the case, arrives at a decision that such person should be exempted from payment of tax in advance or that the rate of payment of tax in advance should be reduced for such person, he may do so and impose such terms and conditions on such person as he may deem fit.

Explanation.—The person, who imports goods into the National Capital Territory of Delhi, shall pay tax in advance, on the presumption that such goods are meant for the purpose of sale or for use in manufacture or processing of goods meant for sale, unless, it is proved otherwise by such person. It is further presumed, unless it is proved otherwise by such person, that such goods or any product manufactured therefrom shall not be sold below the price at which such goods have been purchased and imported.”

**3. Amendment of section 29.**—In the principal Act, in section 29, after sub-section (1), and before the Explanation 1 clause, the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(2) The Commissioner may by notification in the official gazette, require any dealer or class of dealers to file the returns only through electronic mode appending digital signatures or any other electronic identification process and with effect from such date as may be specified therein.”

**4. Insertion of new section.**—In the principal Act, after section 50, the following new section shall be inserted, namely:—

“50A Electronic communication of sale information.—(1) the Government may by notification in the official gazette require any dealer or class of dealers to install such physical compliance devices or software, as may be considered necessary for instantaneous communication of the information of sale invoices to the Commissioner.

(2) The cost of equipment and installation of the device and software, as may be required under sub-section (1), shall be borne by the dealer.”

**5. Amendment of section 89.**—In the principal Act, in section 89,–

(i) in sub-section (1), the concluding words "with a fine", shall be substituted with the words "with a fine of not less than the amount equal to tax deficiency involved or fifty thousand rupees, whichever is higher but not exceeding four times of the amount of tax deficiency involved";

(ii) in sub-section (2), the concluding words "with a fine", shall be substituted with the words "with a fine of not less than the amount equal to tax deficiency involved or fifty thousand rupees, whichever is higher but not exceeding four times of the amount of tax deficiency involved";

(iii) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted namely:-

"(3) Whoever, willfully attempts, in any manner whatsoever, to evade payment of tax, penalty or interest or all of them under this Act, shall, on conviction, be punished-

(a) in any case where the amount involved exceeds one crore rupees during the period of a year, with rigorous imprisonment for a term which may extend from a minimum period of six months to two years, and with a fine of not less than the amount equal to tax deficiency involved or fifty thousand rupees, whichever is higher but not exceeding four times of the amount of tax deficiency involved;

(b) in any case where the amount involved exceeds fifty thousand rupees but does not exceed one crore rupees during the period of a year, with rigorous imprisonment for a term which may extend to six months, and with a fine of not less than the amount equal to tax deficiency involved or fifty thousand rupees, whichever is higher but not exceeding four times of the amount of tax deficiency involved; and

(c) in any other case, with rigorous imprisonment for a term which may extend to three months and with a fine of not less than the amount equal to tax deficiency involved or fifty thousand rupees, whichever is higher but not exceeding four times of the amount of tax deficiency involved."

(iv) in sub-section (4), the concluding words "with a fine", shall be substituted with the words "with a fine of not less than the amount equal to tax deficiency involved or fifty thousand rupees, whichever is higher but not exceeding four times of the amount of tax deficiency involved";

(v) in sub-section (5), the concluding words "with a fine", shall be substituted with the words "with a fine of not less than the amount equal to tax deficiency involved or fifty thousand rupees, whichever is higher but not exceeding four times of the amount of tax deficiency involved"; and

(vi) in sub-section (6), the words "one hundred rupees", shall be substituted with the words "five hundred rupees".

6. **Insertion of new section.**—In the principal Act, after section 91, the following new section shall be inserted, namely:-

**"91A Special Courts and Public Prosecutor.**—(1) Notwithstanding anything contained in this Act to the contrary, the Government may, if considers expedient or necessary, constitute, by notification in the Official Gazette, a Special Court with the concurrence of the Chief Justice of the Delhi High Court for the purposes of the trial of offences under this Act.

(2) For the Special Court, the Government shall appoint a person to be the Public Prosecutor and may appoint more than one person to be the Additional Public Prosecutors."

7. **Amendment of section 92.**—In the principal Act, in section 92,-

(i) in sub-section (2), after the concluding words "a cognizable offence", the words "and all provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973, shall be applicable *mutatis-mutandis*" shall be inserted; and

(ii) after sub-section (2), the following sub-sections shall be inserted, namely:-

"(3) If in a series of acts, so connected, as to form same transaction, any cognizable offence under the Indian Penal Code, 1860 appears to have been committed in addition to offence under this Act, the officers so authorized shall be competent to investigate such cognizable offence under the Indian Penal Code, 1860.

(4) Every officer or person so authorized shall, upon investigation of the offence, submit a report to the Commissioner with the recommendations for sanctioning prosecution or otherwise and the Commissioner, shall, then take a decision as to whether prosecution is essentially required in the matter and if so, the authorized officer shall launch prosecution before the Metropolitan Magistrate having jurisdiction over the area or before a court specially designated by the government for the purpose."

8. **Amendment of section 93.**—In the principal Act, in section 93, in sub-section (1) the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the composition of offence shall not apply in case of second and subsequent offence of the same nature."

5076 D9/15-2

### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Delhi Value Added Tax Act, 2004 is proposed to be amended to incorporate some specific provisions which are necessitated by a variety of compulsive reasons varying from – removal of some discrepancies/anomalies noticed by the department or brought to its notice by the stakeholders from time to time, making the tax administration more efficient and for making some changes required in the public interest.

The proposed amendment in section 3 aim at introducing provisions for levy and collection of advance tax from persons importing goods from outside India and to minimize the chances of evasion of tax by importers thereby making the tax administration more efficient.

The proposed amendment in section 29 will facilitate the dealers in filing the returns through digital signatures or other electronic options, thereby dispensing with the requirement of filing Form DVAT 56 in person in the Department.

Insertion of new section 50A aim at capturing the data of sales made by dealers instantly through electronic communication thereby minimizing the chances of manipulation of any sale data afterwards and evasion of tax thereof.

The proposed amendments in section 89 to make the provisions more deterrent by increasing the punishment for potential offenders including increase of the amount of minimum fine which can be imposed under the provisions of the Delhi Value Added Tax Act, 2004.

The proposal for insertion of new section 91A is to make enabling provisions for setting up of Special Courts for speedy trials of the offences.

The proposed amendment of section 92 aims to empower investigation under the Indian Penal Code, 1860 where commission of an offence under the Delhi Value Added Tax Act, 2004, involves commission of an offence punishable under the Indian Penal Code, 1860 and to incorporate the process to be opted by an authorized officer for prosecution after investigation of an offence.

The amendment in section 93 is to disallow compounding of offences to a habitual offender  
The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

### FINANCIAL MEMORANDUM

The Delhi Value Added Tax (Third Amendment) Bill, 2015 does not involve any additional financial implications since no outgo on new posts is anticipated from the Consolidation Fund of the National Capital Territory of Delhi.

### MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Delhi Value Added Tax (Third Amendment) Bill, 2015 does not make provision for the delegation of power in favour of any functionaries to make subordinate legislation except-

- (i) the delegation under section 2 of this Act for specifying the good and rates of advance tax thereof, terms and conditions and the manner of levy of advance tax.
- (ii) the delegation under section 3 of this Act regarding requirement of filing returns in electronic mode through digital signatures or any other electronic identification process.
- (iii) the delegation under section 4 of this Act for seeking instantaneous information of sale invoices through physical compliance devices or software.
- (iv) the delegation under section 6 of this Act for constitution of Special Courts.

PRASANNA KUMAR SURYADEVARA, Secy.